(ख) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचारार्थ भेजे गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) गत चार वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्रति वर्ष कितना अनुदान प्राप्त हुआ और चालू वर्ष के लिए मध्य प्रदेश को कितनी धनराशि दिये जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई): (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, स्टाफ, उपस्कर, पत्र-पत्रिकाओं, संकाय सुधार, विस्तार कार्यक्रमों, भवनों, पुस्तकालय भवनों, महिला छात्रावासों और अन्य योजना स्वास्थ्य केंद्रों, परिसर विकास जैसे अनुरक्षण और विकास प्रयोजनों के लिए मध्य प्रदेश सहित पात्र विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान करता है।

वर्ष 1992-93 से 1995-96 के दौरान मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदान निम्नानुसार है:-

वर्ष	(रु लाख में) निर्मुक्त अनुदान
1992-93	903.93
1993-94	795.51
1994-95	1098.14
1995-96	1084.57

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा के लिए चालू वर्ष का आवंटन लगभग 1000 करोड़ रु. है।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालयों के विकास प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को नहीं भेजे जाते हैं, बल्कि ये प्रस्ताव स्वयं संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा सीधे ही आयोग को विचारार्थ भेजे जाते हैं।

अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में रेलवे लाइनों का अभाव

*54. **श्री जगन्नाथ सिंह:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में रेलवे लाइनों का अभाव है; और

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में रेल सुविधा प्रदान करने की क्या योजना है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) और (ख) यद्यपि देश में मुख आदिवासी क्षेत्रों में पर्याप्त रेल अवसंरचना उपलब्ध है तथापि कुछ ऐसे आदिवासी क्षेत्र हैं जहां अभी भी रेल लाइनें पर्याप्त नहीं हैं। बहरहाल, आदिवासी बहुल क्षेत्रों सहित पिछड़े क्षेत्रों में इस समय निम्नलिखित नई लाइनें निर्माणधीन हैं:—

(i) अमरावती-नरखेड (महाराष्ट्र में, 138 कि. मी.)

(ii) जोगीघोपा-गुवाहाटी (असम में, 142 कि. मी.)

(iii) पेडापल्ली-निजामाबाद (आन्ध्र प्रदेश में, 117 कि.मी.)

(iv) लांजीगढ़ रोड-जूनागढ़ (उड़ीसा में, 54 कि.मी.)

(v) खोरधा रोड-बोलनगीर (उड़ीसा में, 28 कि.मी.)

(vi) दुमका-मंदारहिल-रामपुरहाट (बिहार में, 130 कि. मी.)

निम्नलिखित लाइनें यद्यपि परियोजना लाइनों के रूप में शुरू की गई हैं तथापि ये पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों को भी सेवित करेंगी और उनके विकास में मदद करेंगी:

(i) तालचेर-संबलपुर (उड़ीसा में, 174 कि. मी.)

(ii) दल्ली राजहरा-जगदलपुर (मध्य प्रदेश में, 235 कि. मी.)

(iii) इंदौर-दाहोद-देवास-मकसी (316 कि.मी., मध्य प्रदेश और गुजरात में)

(iv) दैतारी-बांसपानी (147 कि. मी., उड़ीसा में)

Financial Assistance to States for the Upgradation of Science Laboratories in Schools

*55.SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government provide financial assistance to States for the upgradation of science laboratories in schools; and

(b) if so, the total amount of assistance provided by Government to various States and Union Territories in Government and Government aided secondary/higher secondary schools, during the last three years?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI S.R. BOMMAI): (a) Yes, Sir.